



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 114]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 29, 2000/ज्येष्ठ 8, 1922

No. 114]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 29, 2000/JYAISTHA 8, 1922

वाणिज्य मंत्रालय

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मई, 2000

विषय : यूरोपीय संघ (ई यू) मूल के या वहां से निर्यातित एनिलीन के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करना।

सं. 21/1/2000-डीजीएडी.— मै. हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक कैमिकल्स लिमि. (एच ओ सी एल), नर्मदा केमाटर पैट्रो कैमिकल्स लिमि. (एन सी पी एल), और एनिरॉक्स पिगमेंट्स लिमि., जो घरेलू उद्योग हैं ने सीमा शुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1995-तथा सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन तथा संग्रहण एवं क्षति निर्धारण) नियम, 1995 के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसमें इसके बाद प्राधिकारी कहा गया है) के समक्ष याचिका दायर की है जिसमें यूरोपीय संघ (ई यू) मूल के या वहां से निर्यात किए गए एनिलीन के पाटन का आरोप लगाया गया है, और पाटनरोधी जांच शुरू करने तथा पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

1. **शामिल उत्पाद:** वर्तमान मामले में विचाराधीन उत्पाद यूरोपीय संघ मूल के या वहां से निर्यातित एनिलीन (एनिलीन तेल के नाम से भी ज्ञात) है। एनिलीन एक मूल कार्बनिक रसायन है जो प्रमुख उद्योगों जैसेकि औषधि, भेषज, रंजक और मध्यवर्ती रंजक के लिए अनिवार्य है। एनिलीन का उपयोग कुछ दूसरे उद्योगों जैसेकि रबड़ रसायन, विस्फोटक रेजिन में भी होता है। एनिलीन रबड़ रसायनों, फोटोग्राफिक रसायनों और आइसोसाइनेट्स के लिए एक मध्यवर्ती उत्पाद है। यह एक पारदर्शी तैलीय, रंगहीन (हल्का पीला) द्रव है और प्राइमरी एमीन यौगिक है।

2. एनिलीन सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1995 के अध्याय 29 के सीमाशुल्क उपशीर्ष सं० 2921.41.01 के अतर्गत वर्गीकृत है लेकिन यह वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और किसी भी तरह से वर्तमान जांच के मामले में बाध्यकर नहीं है।

3. **घरेलू उद्योग की हैसियत:** देश में केवल निम्नलिखित तीन कंपनियां एनिलीन का उत्पादन करती हैं:-

- (क) मै० हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक कैमिकल्स लिमि., (एच ओ सी एल)
- (ख) मै० नर्मदा केमाटर पैट्रो कैमिकल्स लिमि., (एन सी पी एल)

(ग) मै0 एनिरॉक्स पिगमेंट्स लिमि.

याचिकाकर्ता द्वारा देश में एनिलीन के समग्र उत्पादन किया जाता है और इस प्रकार वे याचिका दायर करने के हकदार हैं ।

4. संबंधित देश: वर्तमान जांच में शामिल देश यूरोपीय संघ है (जिसे इसमें इसके बाद संबद्ध देश कहा गया है) ।

5. समान वस्तुएं याचिकाकर्ता का कहना है कि उसके द्वारा उत्पादित माल, यूरोपीय संघ के मूल के या वहां से निर्यातित माल के समान वस्तुएं हैं । याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित माल को नियमावली के अर्थों के भीतर संबद्ध देशों से आयातित माल के समान वस्तुएं माना जा रहा है ।

6. पाटन एवं पाटन मार्जिन

सामान्य मूल्य: याचिकाकर्ता ने यूरोपीय संघ में सामान्य मूल्य का दावा यूरोपीय संघ में एक व्यापार पत्रिका कैमिकल वीक में दी गई कीमतों के आधार पर किया है । संबद्ध देशों में एनिलीन के सामान्य मूल्य के संबंध में प्रथमदृष्टया पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं ।

निर्यात कीमत: याचिकाकर्ता ने निर्यात कीमत का दावा डीजीसी आई एंड एस, कलकत्ता और कांडला पत्तन द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के आधार पर किया है ।

सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए पाटन मार्जिन न्यूनतम सीमा से काफी अधिक है ।

प्रथमदृष्टया इस बात के पर्याप्त साक्ष्य हैं कि यूरोपीय संघ में विचाराधीन उत्पाद का सामान्य मूल्य भारत में निर्यात किए गए मूल्य की तुलना में काफी अधिक है और यह कि यूरोपीय संघ के निर्यातक संबद्ध वस्तुओं का पाटन कर रहे हैं ।

7. क्षति और कारणात्मक संबंध: घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न आर्थिक संकेतकों जैसेकि उत्पादन, बिक्री लाभ/हानि इत्यादि समग्र तथा संचयी रूप से यह संकेत देते हैं कि घरेलू उद्योग को क्षति हुई है । प्रथमदृष्टया इस बात के पर्याप्त साक्ष्य हैं कि विचाराधीन उत्पाद के आयात से घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है ।

8. पाटनरोधी जांच का आरंभ: उपरोक्त को देखते हुए, निर्दिष्ट प्राधिकारी, संबद्ध देशों के मूल के या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं की कथित डम्पिंग होने, उसकी मात्रा तथा उसके प्रभाव के निर्धारण के लिए पाटन रोधी जांच आरंभ करते हैं ।

9. **जांच की अवधि:** वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए जांच की अवधि 1 अप्रैल, 1999 से 31 दिसम्बर, 1999 (9 महीनों) की है।

10. **सूचना प्रस्तुत करना:** संबद्ध देशों में निर्यातकों और भारत में आयातकों को अलग से लिखा जा रहा है कि वे अपने विचार तथा संबंधित सूचना निर्धारित रूप में तथा निर्धारित ढंग से निर्दिष्ट प्राधिकारी भारत सरकार वाणिज्य विभाग, पाटनरोधी तथा संबद्ध शुल्क निदेशालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011 को भेज दें। अन्य कोई हितबद्ध पार्टी भी नीचे दी गई समयावधि की सीमा के भीतर निर्धारित रूप में और निर्धारित ढंग से जांच से संबंधित अभिवेदन दे सकती हैं।

11. **समय सीमा:** वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना लिखित रूप में दी जाए जो उपरोक्त पते पर निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से 40 दिनों के भीतर पहुंच जानी चाहिए। तथापि, जिन ज्ञात निर्यातकों और आयातकों को अलग से लिखा जा रहा है, उन्हें अलग से लिखे गए पत्र की तारीख से 40 दिनों के भीतर सूचना देनी होगी।

12. पाटनरोधी जांच एक समयबद्ध कार्यवाही होने के कारण, निर्दिष्ट प्राधिकारी उक्त नियम के अनुसार रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकता है, अगर निर्धारित समय के अंदर कोई उत्तर नहीं मिलता है या सूचना किसी भी रूप से अपूर्ण होती है।

13. **सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण:** नियम 6(7) के अनुसार कोई भी इच्छुक पार्टी उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकती है जिसमें अन्य हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के अगोपनीय अंश रखे गए हैं।

14. यदि कोई हितबद्ध पार्टी आवश्यक सूचना जुटाने से मना करती है या उचित समय के भीतर उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराती है या महत्वपूर्ण ढंग से जांच में बाधा डालती हैं तो प्राधिकारी, अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकता है तथा केन्द्रीय सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकता है।

रति विनय झा, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 29th May, 2000

Subject: Initiation of anti-dumping investigations concerning import of Aniline originating in or exported from European Union (EU).

No. 21/1/2000-DGAD.—M/s. Hindustan Organic Chemicals Ltd. (HOCL), Narmada Chematur Petro Chemicals Ltd. (NCPL), and Anirox Pigments Ltd., forming the domestic industry have filed a petition before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) in accordance with the Customs Tariff (Amendment) Act, 1995 and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 alleging dumping of Aniline originating in or exported from European Union (EU) and have requested for initiation of anti dumping investigations and levy of anti-dumping duties.

1. Product Involved: The product under investigation in the present case is Aniline (also known as Aniline Oil) originating in or exported from EU. Aniline is a basic organic chemical essential for vital industries such as Drugs, Pharmaceuticals, Dyes and Dye Intermediates. Aniline is also used in some other industries such as Rubber Chemicals, Explosives and Resins. Aniline is an intermediate for Rubber Chemicals, Photographic Chemicals, and Isocyanates. It is a transparent, oily liquid and is a primary amine compound.

2. Aniline is classified under Customs sub-heading nos. 2921.41.01 of Chapter 29 of the Customs Tariff Act, 1975. The classification is however indicative only and in no way binding on the scope of the present investigations.

3. Domestic Industry Standing: The following three companies are the only producers of Aniline in the country:-

- (a) M/s. Hindustan Organic Chemicals Ltd., (HOCL),
- (b) M/s. Narmada Chematur Petro Chemicals Ltd., (NCPL),
- (c) M/s. Anirox Pigments Ltd.

The petitioners represent total production of Aniline in the country and thus have the standing to file the petition.

4. Country(ies) Involved: The country involved in the present investigations is European Union (referred to as subject country hereinafter).

5. Like Goods: The petitioner has claimed that goods produced by it are like articles to the goods originating in or exported from EU. Goods produced by the petitioner are being treated as Like Articles to the goods imported from the subject countries within the meaning of the Rules.

6. Dumping and Dumping Margin:

Normal Value: The petitioner has claimed normal value in Europe on the basis of Aniline prices reported in a trade journal – Chemical Week in EU. There is sufficient prime facie evidence with regard to normal value of Aniline in the subject country.

Export Price: The petitioner has claimed export price based on the data published by the DGCI & S, Calcutta and Kandla Port.

Considering the normal value and export price, the dumping margins are significantly higher than the de-minimus limits.

There is sufficient prima facie evidence that the normal value of the product under consideration in EU is significantly higher than the price at which it has been exported to India, and that the exporters from EU are dumping the subject goods.

7. Injury and Causal Link: The various economic indicators relating to domestic industry such as production, sales, profit/loss etc. collectively and cumulatively, indicate that the domestic industry has suffered injury. There is sufficient prima facie evidence that the import of product under consideration have caused material injury to the domestic industry.

8. Initiation of Anti-Dumping Investigation: In view of the foregoing, the Designated Authority initiates anti-dumping investigations to determine the existence, degree and effect of alleged dumping of the subject goods originating in or exported from the subject countries.

9. Period of Investigation: The period of investigation for the purpose of the present investigations is 1st April, 1999 to 31st December, 1999 (9 months).

10. Submission of Information: The exporters in the subject countries and the importers in India known to the concerned are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Designated Authority, Ministry of Commerce, Directorate General of Anti dumping and Allied Duties, Udyog Bhavan, New Delhi-110011. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

11. Time Limit: Any information relating to the present investigations should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days from the date of publication of this notification. The known exporters and importers, who are being addressed separately, are, however, required to submit the information within forty days from the date of letter addressed to them separately.

12. Anti-dumping investigations being a time bound exercise, the Designated Authority may record its findings on the basis of facts available on record in accordance with the Rules supra, if no response is received within the time stipulated or the information is incomplete in any respect.

13. Inspection of Public File: In terms of Rule 6(7), any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties.

14. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

RATHI VINAY JHA, Designated Authority

1528 GI/2000-2

